भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1500

(28 जुलाई, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए)

पीएमएवाई-जी के तहत आवास+ सर्वेक्षण

1500. श्री मड्डीला गुरूमूर्ति:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विस्तारित आवास+ 2024 सर्वेक्षण अवधि के दौरान आंध्र प्रदेश में पहचाने गए नए पात्र ग्रामीण परिवारों का ब्यौरा और उनकी कुल संख्या कितनी है, तथा इन नए प्रविष्टियों के सापेक्ष बाद में स्वीकृत किए गए मकानों की संख्या कितनी है;

(ख) चरण-I और वर्तमान में चल रहे चरण-II के अंतर्गत आंध्र प्रदेश में स्वीकृत, निर्माण कार्य शुरू किए गए और पूरे किए गए प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के मकानों की कुल संख्या कितनी है, तथा पिछले दो वित्तीय वर्षों के दौरान राज्य को जारी की गई कुल केंद्रीय निधि का ब्यौरा क्या है;

(ग) राज्य के जनजातीय समुदायों में पूर्ण संतृप्ति प्राप्त करने के लिए विशेष पीएम-जनमन आवास घटक के तहत आंध्र प्रदेश में स्वीकृत और पूरे किए गए मकानों की कुल संख्या कितनी है; और

(घ) प्रक्रियात्मक बाधाओं को दूर करने और ग्रामीण लाभार्थियों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) में तेजी लाने के लिए मंत्रालय द्वारा राज्य में आयोजित क्षेत्रीय ग्रामीण कार्यशालाओं के स्पष्ट परिणाम क्या हैं?

उत्तर

ग्रामीण विकास राज्य मंत्री

(डॉ. चंद्र शेखर पेम्मासानी)

(क) आंध्र प्रदेश राज्य में 2,910 स्व-सर्वेक्षण मामलों सहित 10,42,199 परिवारों का सर्वेक्षण किया गया है। वर्तमान में आंध्र प्रदेश सहित सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र आवास+ 2024 परिवार

सर्वेक्षण से स्थायी प्रतीक्षा सूची को अंतिम रूप देने के लिए प्रारूप प्राथमिकता सूची तैयार करने और ग्राम सभा आयोजित करने संबंधी कार्यकलाप कर रहे हैं।

आवास+ 2024 परिवार सर्वेक्षण के आंकड़ों के विश्लेषण के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित की गई थी। विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों को मंत्रालय द्वारा स्वीकार कर लिया गया है। मंत्रालय द्वारा अनुमोदित इस विशेषज्ञ समिति की सिफारिश के आधार पर, वित्त वर्ष 2026-27 के दौरान आवास+ 2024 परिवार सर्वेक्षण से आंध्र प्रदेश राज्य को 74,212 आवासों का लक्ष्य आवंटित किया गया है। ग्राम सभा द्वारा स्थायी प्रतीक्षा सूची को अंतिम रूप दिए जाने के आधार पर राज्य द्वारा वास्तविक स्वीकृति की जाती है।

(ख) पीएमएवाई-जी के तहत, आंध्र प्रदेश राज्य में 23 जुलाई, 2026 तक संचयी रूप से 2,46,929 आवास स्वीकृत किए गए हैं और 90,594 आवास निर्मित किए गए हैं। मंत्रालय द्वारा आवंटित चरणवार लक्ष्यों की तुलना में प्रगति निम्नानुसार है:

चरण-I/II	**मंत्रालय द्वारा आवंटित लक्ष्य**	**राज्य द्वारा स्वीकृत आवास**	**निर्मित आवास**	**लक्ष्य की तुलना में अपूर्ण/निर्माणाधीन आवास**
चरण-I	2,46,430	2,46,425	90,486	1,55,944
चरण-II	74,896	504	108	74,788
संचयी	**3,21,326**	**2,46,929**	**90,594**	**2,30,732**

पीएमएवाई-जी के कार्यान्वयन हेतु पिछले दो वित्तीय वर्षों अर्थात् वित्त वर्ष 2024-25 और 2025-26 के दौरान आंध्र प्रदेश राज्य को केंद्रीय अंश के रूप में 1.89 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।

(ग) प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम जनमन) के आवास कार्यकलाप के अंतर्गत, 23.07.2026 तक आंध्र प्रदेश राज्य में कुल 43,592 आवास स्वीकृत किए गए हैं और 9,804 आवास निर्मित किए गए हैं।

(घ) पीएमएवाई-जी के कार्यान्वयन कि रुपरेखा के एक भाग के रूप में, क्षेत्रीय ग्रामीण कार्यशालाएं आयोजित की जाती हैं जिनमें यह कार्यशाला राज्य अधिकारियों की क्षमता निर्माण को सुगम बनाती है और स्वीकृति, निधि प्रवाह तथा प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से किस्तों के जारी होने से संबंधित प्रक्रियागत एवं तकनीकी बाधाओं तथा मुद्दों सहित कार्यान्वयन प्रगति की समीक्षा हेतु एक मंच प्रदान करती है। राज्य में अंतिम ऐसी कार्यशाला 21-22 अक्तूबर, 2024 को गुंटूर, आंध्र प्रदेश में आयोजित की गई थी।

*****

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT
DEPARTMENT OF RURAL DEVELOPMENT

LOK SABHA
UNSTARRED QUESTION NO. 1500
TO BE ANSWERED ON 28/07/2026

Awaas+ Survey under PMAY-G

1500. Shri Maddila Gurumoorthy:

Will the Minister of RURAL DEVELOPMENT be pleased to state:
(a) the details and total number of new eligible rural households identified in Andhra Pradesh during the extended Awaas+ 2024 survey window, and the number of houses subsequently sanctioned against these fresh entries;
(b) the cumulative number of Pradhan Mantri Awas Yojana-Gramin (PMAY-G) housing units sanctioned, grounded and completed in Andhra Pradesh across Phase-I and the ongoing Phase-II operations, along with the total Central funds released to the State during the last two financial years;
(c) the total number of houses sanctioned and completed in Andhra Pradesh under the dedicated PM-JANMAN housing component to achieve saturation across the State's tribal communities; and
(d) the measurable outcomes of the Regional Rural Workshops organized by the Ministry in the State to clear procedural bottlenecks and expedite Direct Benefit Transfers (DBT) to rural beneficiaries?

ANSWER

MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT
(DR. CHANDRA SEKHAR PEMMASANI)

(a) In the State of Andhra Pradesh, 10,42,199 households have been surveyed including 2,910 Self-Survey cases. At present all States/Union Territories including Andhra Pradesh are undertaking activities related to generation of draft priority lists and conduct of Gram Sabha for finalization of the Permanent Wait List from Awaas+ 2024 household Survey.

An Expert Committee was constituted to analyse the Awaas+ 2024 household Survey data. The recommendations of the Expert Committee have been accepted by the Ministry. Based on the recommendation of this Expert Committee as approved by the Ministry, a target of 74,212 houses from Awaas+ 2024 household Survey has been allocated to the State of Andhra Pradesh during FY 2026-27. The actual sanctioning is done by the State based on the finalization of the Permanent Wait List by Gram Sabha.

(b) Under the PMAY-G, cumulative 2,46,929 houses have been sanctioned and 90,594 houses completed, till 23rd July 2026 in the State of Andhra Pradesh. The progress against phase-wise targets allocated by Ministry is given as under:

Phase-I/ II	Target allocated by Ministry	Houses sanctioned by State	Houses completed	Incomplete/ Ongoing houses against target
Phase-I	2,46,430	2,46,425	90,486	1,55,944
Phase-II	74,896	504	108	74,788
Cumulative	3,21,326	2,46,929	90,594	2,30,732

An amount of Rs. 1.89 crore has been released as the Central Share to the State of Andhra Pradesh during last two financial years i.e. FY 2024-25 and 2025-26 for implementation of the PMAY-G.

(c) Under the Housing Intervention of the Pradhan Mantri Janjati Adivasi Nyaya Abhiyan (PM JANMAN), a total of 43,592 houses have been

sanctioned and 9,804 houses have been completed in the State of Andhra Pradesh, till 23.07.2026.

(d) As a part of the framework for implementation of PMAY-G, regional rural workshops are held wherein the workshop facilitates capacity building of State officials and provides a platform to review implementation progress, including procedural and technical bottlenecks and issues relating to sanctioning, fund flow and release of instalments through Direct Benefit Transfer (DBT). The last such workshop in the State was held on 21st-22nd October, 2024 at Guntur, Andhra Pradesh.

*****